Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

अक्टूबर 2022 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- सौर कृषि आजीविका योजना 3
- प्रतापगढ़ ज़िले के लिये 1062.77 करोड़ की बृहद् परियोजना स्वीकृत 3
- राजस्थान में शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन 4
- राजस्थान में 1.42 लाख करोड़ के 32 निवेश प्रस्तावों को मज़ूरी 4
- 'राजस्थान रत्न' पुरस्कार 4
- प्रदेश में गांधी जयंती पर 1.5 करोड़ लोगों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड 5
- मुख्यमंत्री ने किया 472 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास 5
- 'इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022' 6
- मुख्यमंत्री ने पैलेस ऑन व्हील्स का किया पुन: संचालन 7
- राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना को मिली मंज़ूरी 7
- जयपुर में आयोजित होगा इंडिया स्टोनमार्ट का 11वाँ संस्करण 8
- जयपुर में आयोजित होगा 'द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवाड्र्स 2022- राजस्थान' 8
- 26वाँ राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 9
- राजस्थान में पेयजल की गुणवत्ता जाँच के लिये स्थापित होंगी 250 नई प्रयोगशालाएँ 9
- राजस्थान को 67 वर्ष बाद मिला राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी की मेज़बानी का अवसर 10
- जस्टिस पंकज मिथल बने राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश 10
- मुख्यमंत्री ने दी पृथ्वीराज नगर के लिये 747 करोड़ रुपए की पेयजल योजना को स्वीकृति 11
- भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान-2022 11
- ऊर्जा मंत्री ने सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल का शुभारंभ किया 12
- राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित जयपुर में सिटी पार्क का लोकार्पण 13
- अस्पतालों में स्थापित होंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 14
- प्रदेश में 124 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुले 14
- प्रत्येक राजकीय भवन की होगी जिओ-टैगिंग 14
- राजस्थान के पुलिस विभाग में 500 मोबाइल यूनिट्स का होगा गठन 15
- 'चंबल-धौलपुर-भरतपुर बृहद् पेयजल परियोजना' के सर्वे एवं डीपीआर कार्यों के लिये मिली वित्तीय स्वीकृति 15
- राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन 16
- राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित 16
- राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 17
- राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 लागू 17
- मुख्यमंत्री ने राजस्थान में विभिन्न बोर्ड के गठन को मंज़ूरी दी 18
- राजस्थान के 344 आवासीय विद्यालयों में स्थापित होंगी डिजिटल लाइब्रेरी 19
- राष्ट्रीय युवा योजना के सातदिवसीय राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना शिविर की शुरुआत 19
- ईसरदा पेयजल परियोजना के लिये 6 नए कार्यालयों के गठन को मंजूरी 20
- राजस्थान में उद्योगों को ईटीपी लगाने के लिये 13.88 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी 20
- डॉ. भीमराव अंबडेकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 21
- राज्य में स्थापित होगा ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 21
- मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के प्रारूप को दी मंज़ूरी 22
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट 22
- जोधपुर में हुआ दो-दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन 23

नोट :

राजस्थान

सौर कृषि आजीविका योजना

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता के लिये 'सौर कृषि आजीविका योजना' को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- 'सौर कृषि आजीविका योजना' से किसानों को अपनी अनुपयोगी भूमि लाभकारी लीज़ दर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिये देकर आजीविका उपार्जित करने में सुविधा होगी तथा उनका जीवन-स्तर ऊपर उठेगा।
- योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जहाँ किसान/भूमि मालिक अपनी ज़मीन को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिये लीज पर देने हेतु पंजीकृत करा सकते हैं।
- भूमि विकासकर्त्ता उक्त किसानों द्वारा पोर्टल पर डाला गया भूमि विवरण देख सकते हैं तथा नियमानुसार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।
- सौर कृषि आजीविका योजना से विकासकर्त्ता भी संयंत्र स्थापित करने के लिये सुगमता से पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्रीय अनुदान (लागत का 30 प्रतिशत) प्राप्त कर सकेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा भूमि मालिक/किसान, विकासकर्त्ता तथा संबंधित डिस्कॉम या कंपनी के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा, ताकि भूमि मालिक/किसान को जोखिम से सुरक्षा प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो सके।
- इस निर्णय से सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान को एक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकेगा तथा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम होने से पर्यावरण प्रदूषण का स्तर कम होगा तथा आमजन को राहत मिलेगी।

प्रतापगढ़ ज़िले के लिये 1062.77 करोड़ की बृहद् परियोजना स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2022 को राजस्थान के जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने राज्य के प्रतापगढ़ ज़िले के लिये 1062 करोड़ 77 लाख रुपए की बृहद् परियोजनाओं की स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रतापगढ़ ज़िले के प्रतापगढ़, अरनोद एवं पीपलखूंट क्षेत्र के 524 गाँवों को जाखम बांध से हर घर जल उपलब्ध कराने के लिये इन परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है।
- इस पेयजल योजना में जाखम बांध से प्रतापगढ़ ज़िले की प्रतापगढ़ पंचायत समिति के 136, धमोत्तर के 106, अरनोद के 83, दलोट के 103 एवं सुहागपुरा पंचायत समिति के 96, यानी कुल 524 गाँवों एवं ढाणियों की पेयजल समस्या का समाधान होगा।
- यह परियोजना वर्ष 2053 की अभिकल्पित आबादी 6 लाख 17 हज़ार 407 को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल मांग को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस परियोजना से जल जीवन मिशन के तहत 82 हज़ार 525 हर घर जल कनेक्शन दिये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि बांसवाड़ा ज़िले की कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ पंचायत समिति के 399 गाँवों को भी माही बांध से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये 211 करोड़ 60 लाख रुपए की पेयजल परियोजना को भी प्रशासनिक एवं वित्तीय मंज़ूरी दी गई है।

नोट :

राजस्थान में शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन

चर्चा में क्यों ?

1 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निदेशालय को विभाग बनाने की घोषणा के बाद राज्य केबिनेट में लिये गए शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- शांति एवं अहिंसा विभाग के ज़रिये शांति और अहिंसा के विचारों का प्रचार-प्रसार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विभिन्न महापुरुषों, वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, शांति और सद्भाव, सामाजिक एकता से संबंधित विभिन्न प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कायक्रमों के आयोजन के लिये समग्र योजना तैयार कर वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- साथ ही, विभाग द्वारा महात्मा गांधी के विचारों एवं सिद्धातों पर आधारित शांति और अहिंसा, साम्प्रदायिक एकता, सामाजिक समानता, सार्वभौमिक भाईचारा, अस्पृश्यता, सामाजिक सुधार से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर उनके क्रियान्वयन के लिये उचित कदम उठाए जाएंगे।
- विभाग द्वारा गांधी सद्भावना सम्मान जैसे विभिन्न पुरस्कारों के लिये, प्राप्त प्रस्तावों के लिये समिति का गठन भी किया जाएगा।

राजस्थान में 1.42 लाख करोड़ के 32 निवेश प्रस्तावों को मज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

2 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तीसरी बैठक में राज्य में42 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये 32 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि इंवेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियों के लिये विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि यह समिट राज्य के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे राज्य में 32 हज़ार से अधिक लोगों के लिये रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों में प्रमुख रूप से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एन्योर पावर प्राइवेट लिमिटेड, रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड आदि, प्लास्टिक एवं ग्लास निर्माण में असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में हीरो इलेक्ट्रिक वाहन, ओकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड के अतिरिक्त कपड़ा, खान एवं खनिज, पूड एवं बेव्रेजेज, आतिथ्य, सीमेंट, ऑटो एवं ऑटो कंपोनेंट और कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण की परियोजनाओं को बोर्ड द्वारा मंज़ूरी दी गई है।
- मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिये अनेक महत्त्वपूर्ण नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया है, जैसे- राजस्थान में एमएसएमई नीति-2022, हस्तशिल्प नीति-2022, पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस-2019), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 एवं वन स्टॉप शॉप सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के राज्य में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को और मज़बूती मिलेगी।
- मुख्यमंत्री गहलोत ने जैसलमेर संभाग में सीमेंट उद्योग के विकास की संभावनाओं के लिये अध्ययन के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के लिये पर्याप्त कच्चा माल, जैसे- लाइमस्टोन आदि उपलब्ध हैं।

'राजस्थान रत्न' पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

3 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'राजस्थान रत्न' पुरस्कार के लिये चुने गए व्यक्तियों के नामों की घोषणा की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष 'राजस्थान रत्न' पुरस्कार से न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा, उद्योगपति अनिल अग्रवाल, उद्योगपति एलएन मित्तल, शीन कौफ निजाम और केसी मालू को सम्मानित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 7 और 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राजस्थान शिखर सम्मेलन के दौरान गणमान्य व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस सम्मेलन में भारत और विदेशों से लगभग 3,000 प्रतिभागी भाग लेंगे।
- विदित है कि 'राजस्थान रत्न', राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस अवार्ड की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। साल 2012 से यह अवार्ड हर साल दिया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न' है। उसी के तर्ज़ पर राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'राजस्थान रत्न' है। राजस्थान रत्न अवार्ड में 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

प्रदेश में गांधी जयंती पर 1.5 करोड़ लोगों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

2 अक्टूबर, 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स संस्था ने विश्व अहिंसा दिवस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदेश भर में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिये कला एवं संस्कृति विभाग को प्रोविजनल प्रमाण-पत्र दिया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बीडी कल्ला, प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और संयुक्त शासन सचिव पंकज ओझा ने यह प्रमाण-पत्र सौंपा।
- उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर को राज्य भर में आयोजित सभा में प्रदेश के गणमान्य लोग, गांधीवादी, विचारक चिंतक, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी, स्वयं सहायता समूह, राजीविका समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप, अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण एवं आमजन द्वारा सहभागिता कर लगभग15 करोड़ लोगों ने यह विश्व रिकॉर्ड बनाया।

मुख्यमंत्री ने किया 472 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

6 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 472 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कर प्रदेशवासियों को सौगात दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने 250 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एल.आई.सी. भवन से सोडाला तक एलीवेटेड रोड का लोकार्पण किया, जिससे जयपुरवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने एलीवेटेड रोड का नाम 'भारत जोड़ो सेतु'रखने की घोषणा भी की।
- इसके अलावा उन्होंने 222 करोड़ रुपए की लागत की 6 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया-
  - संकल्प नगर-सांझरिया में 43 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का शिलान्यास
  - राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर परिसर में गेस्ट हाउस का शिलान्यास
  - पृथ्वीराज नगर (उत्तर) में 1200 एम.एम. व्यास की मुख्य ट्रंक लाइन का शिलान्यास
  - पृथ्वीराज नगर (उत्तर) में 600-900 एम.एम. व्यास की मुख्य ट्रंक लाइन का शिलान्यास
  - लुनियावास-गोनेर रोड पर ड्रेनेज कार्य का शिलान्यास
  - वंदेमातरम् रोड-मुहाना मंडी रोड पर मुख्य ड्रेनेज कार्य का शिलान्यास

नोट :

'इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022'

चर्चा में क्यों ?

7 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेईसीसी सीतापुरा, जयपुर में आयोजित दोदिवसीय 'इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022' का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस दोदिवसीय समिट में दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट समूहों के गणमान्य व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। समिट के तहत आयोजित कॉन्क्लेव एवं पैनल डिस्कशन में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एवं लीडर्स द्वारा अपने अनुभव साझा किये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दोदिवसीय समिट से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। समिट से पूर्व ही निवेशकों के साथ राज्य सरकार द्वारा लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू कर लिये गए हैं। इसके ज़रिये लगभग 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। पहली बार 'कमिटेड एंड डिलिवर्ड'की थीम पर प्राथमिकता के साथ एमओयू साईन किये गए हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न ज़िलों में 25 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने 18 औद्योगिक इकाईयों का लोकार्पण व 33 औद्योगिक इकाईयों का शिलायास भी किया। उक्त शिलान्यास व लोकार्पण से जहाँ एक ओर राज्य में विभिन्न ज़िलों में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर रोज़गार व राजस्व में वृद्धि होगी।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट व असाधारण कार्यों से देश-विदेश में राजस्थान को गौरवान्वित करने वाली 6 विभूतियों को 'राजस्थान रत्न सम्मान' से सम्मानित भी किया। इन सभी को प्रशस्ति-पत्र, शॉल, मोमेन्टो व 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया।
- इनमें न्याय के क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश दलवीर भंडारी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा, उद्योग के क्षेत्र से वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन एलएन मित्तल तथा कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध निर्माता केसी मालू व प्रसिद्ध उर्दू शायर शीन काफ निजाम को 'राजस्थान रत्न' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- समिट के पहले दिन 5 कॉन्क्लेव- एनआरआर, टूरिज्म, स्टार्ट-अप, एग्री-बिज़नेस और फ्यूचर रेडी सेक्टर पर कॉन्क्लेव आयोजित किये गए, जबकि समिट के दूसरे दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने नॉन रेजीडेंट राजस्थानी (एनआरआर) कॉन्क्लेव सत्र के दौरान पहली नॉन रेजीडेंट राजस्थानी (एनआरआर) पॉलिसी और राजस्थान फाउंडेशन की वेबसाइट को भी लॉन्च किया।
- समिट के अंतर्गत आयोजित फ्यूचर रेडी सेक्टर कॉन्क्लेव- एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर रेडी सेक्टर्स को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राजस्थान देश में पहला प्रदेश होगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करेगा।
- उल्लेखनीय है कि इस समिट के आयोजन के लिये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) को नेशनल पार्टनर नियुक्त किया गया है, जो समिट के आयोजन के लिये राज्य सरकार को सहयोग प्रदान कर रहा है।
- मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान 'राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022' (रिप्स-2022) भी लॉन्च की। इसके अंतर्गत राज्य में व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजित करने वाले, अनुसूचित जनजाति/जाति के उत्थान में योगदान देने वाले तथा क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 के अंतर्गत इस प्रकार के उद्योगों के लिये कई तरह की सब्सिडी तथा आईजीएसटी पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने पैलेस ऑन व्हील्स का किया पुन: संचालन

चर्चा में क्यों ?

8 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 वर्षों से बंद पड़ी पैलेस ऑन व्हील्स शाही ट्रेन को जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी का संचालन कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से बंद था। पिछले 40 वर्षों से चल रही इस ट्रेन का 2 वर्षों के अंतराल के बाद पुन: प्रारंभ होना यह इंगित करता है कि आने वाले दिनों में राज्य में पर्यटन क्षेत्र और मज़बूती के साथ उभरेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस शाही रेलगाड़ी को आरटीडीसी व पर्यटन विभाग की सकारात्मक पहल से पुन: शुरू किया गया है। रेलवे और आरटीडीसी के संयुक्त तत्वावधान में इस ट्रेन में आधुनिक साज-सज्जा और सभी पर्यटक सुख-सुविधाओं का समावेश किया गया है।
- उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान की पुरानी हवेलियाँ, गढ़, किले और रेगिस्तान के साथ लोक कलाएँ, हस्तशिल्प आदि की दुनिया भर में खास पहचान है।
- उन्होंने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान देश का सबसे संपन्न राज्य है और दिल्ली-आगरा के बाद विदेशी पर्यटक राजस्थान आना पसंद करते हैं। यहाँ स्वदेशी पर्यटन की समृद्ध परंपरा रही है। वर्ष 2022-23 के बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 1000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि प्रथम शाही रेल वर्ष 1982 में प्रारंभ हुई थी। रेलवे द्वारा समय-समय पर रेल की गेज परिवर्तन के फलस्वरूप मीटर गेज से ब्रॉड गेज ट्रेन वर्ष 1991 में दूसरी और 1995 में तीसरी शाही रेल का निर्माण किया गया।
- शाही रेलगाड़ी का दिल्ली व आगरा के अलावा राजस्थान के खूबसूरत शहरों- जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर तथा भरतपुर का सफर सात दिन में तय करेगा।
- राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के दर्शन कराती इस शाही रेल का सफर देशी और विदेशी पर्यटकों को आनंदित करता है। यहाँ पर पर्यटक अपने आप को राजसी माहौल में पाता है। इसमें आवभगत, स्वादिष्ट व्यंजन और पर्यटन निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा भावना व अतिथि सत्कार को देखकर पर्यटक रोमांचित होते हैं।

राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

10 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिये 'राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना' को लागू करने की मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में वर्ष 2022-23 में एक लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिये 2 हज़ार करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार इस ऋण के लिये पात्र होंगे। यह ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाईनेंस बैंकों के माध्यम से मिलेगा। राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिये 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देगी।
- सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि योजना में अन्य पात्रता मापदंडों की पूर्ति करने वाले लघु एवं सीमांत कृषक तथा भूमिहीन श्रमिक, जो कि किराएदार, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार आदि के रूप में काश्त कर रहे हैं, के परिवार भी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण दस्तकार तथा अकृषि कार्यों में जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवार के सदस्य भी पात्र होंगे।

नोट :

- इसके साथ ही राजीविका के स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों एवं व्यावसायिक समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिये ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रति समूह अधिकतम 10 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से ऋण दिया जाएगा एवं ऋण की अधिकतम राशि 2 लाख रुपए होगी।
- उन्होंने बताया कि ऋण के लिये आवेदक का बैंक शाखा के कार्य क्षेत्र अथवा ज़िले का निवासी होना ज़रूरी है तथा उसका आधार एवं जनाधार बना हो। परिवार के सदस्य के पास किसी भी लाईसेंसधारी बैंक से जारी किया हुआ किसान कार्ड होना चाहिये। जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हो, उनको नए सदस्य के रूप में अकृषि कार्यों हेतु क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया जाएगा। आवेदक से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी।
- मंत्री आंजना ने बताया कि आवेदक को संपूर्ण ऋण साख सीमा के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। साख सीमा राशि का आकलन व्यवसाय की पूंजीगत आवश्यकताओं, कार्यशील पूंजी तथा रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। स्वीकृत साख सीमा का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाना होगा, अर्थात् एक वर्ष पूर्ण होने पर खाते में बकाया राशि जमा करवाकर साख सीमा को अगले वर्ष के लिये नवीनीकृत करवाना होगा। इस योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्षों में भी निरंतर ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।
- उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 55 हज़ार 158, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 36 हज़ार 741, सहकारी बैंकों द्वारा 5 हज़ार 949 तथा स्माल फाईनेंस बैंकों द्वारा 2 हज़ार 152 सहित कुल एक लाख ग्रामीण परिवारों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्वीकृत ऋण राशि की अदायगी एक वर्ष की अवधि में करनी होगी तथा ऋणी आगामी वर्ष के लिये साख सीमा का नवीनीकरण करवा सकेगा।
- ज़िला कलेक्टर द्वारा ज़िले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से पात्र परिवार का चयन किया जाएगा। पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी पात्रता मापदंडों का परीक्षण कर ऋण आवेदन-पत्र संबंधित बैंक शाखा को भेजेगी। शाखा 15 दिवस में ऋण स्वीकृति पर निर्णय लेगी।

जयपुर में आयोजित होगा इंडिया स्टोनमार्ट का 11वाँ संस्करण

चर्चा में क्यों ?

11 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान की मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने जयपुर के शासन सचिवालय में इंडिया स्टोनमार्ट के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि इंडिया स्टोनमार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 13 नवंबर को जयपुर के जेईसीसी में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने इंडिया स्टोनमार्ट-2022 के संबंध में संबंधित अधिकारियों को समुचित तैयारियाँ सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि देश-विदेश में प्रसिद्ध इंडिया स्टोनमार्ट का आयोजन ऐतिहासिक होना चाहिये।
- इंडिया स्टोनमार्ट का आयोजन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, रिको और फिक्की द्वारा किया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पुलिस, सामान्य प्रशासन विभाग सहित अन्य विभाग इसको सफल बनाने के लिये सहयोग देंगे।
- इंडिया स्टोनमार्ट में लगभग 350 प्रदर्शकों के भाग लेने की संभावना है। इसमें टर्की, ईरान, पुर्तगाल सहित कई देशों के प्रदर्शक भाग लेंगे। गुजरात और ओडिशा राज्य भी इसमें स्टेट पवेलियन लगाएंगे। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल, बायर-सेल मीट व शिल्पग्राम का आयोजन भी यहाँ किया गया है।

जयपुर में आयोजित होगा 'द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवाड्र्स 2022- राजस्थान'

चर्चा में क्यों ?

11 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के पर्यटन विभाग की निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि 'द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवाड्र्स 2022-राजस्थान' जयपुर में नवंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि राज्य में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने वाले उद्यमियों को सम्मानित करने के लिये राजस्थान पर्यटन विभाग ने आउटलुक ग्रुप के सहयोग से 'द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवाड्र्स 2022-राजस्थान'की शुरुआत की है। इसमें पर्यटन क्षेत्र से जुड़े स्थानीय उद्यमी भाग लेंगे।
- उन्होंने बताया कि 'द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवाड्र्स 2022-राजस्थान'आठ श्रेणियों में दिये जाएंगे।
- ये अवाड्र्स सस्टेनेबल लीडरशिप- होटल्स, सस्टेनेबल लीडरशिप- होमस्टे, सस्टेनेबल लीडरशिप- बीएनबी और गेस्टहाउस, सस्टेनेबल इंटरप्राइजेज इन ईको फ्रैंजाइल लेंडस्कैप, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन इन पाथफाइंडर, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन इन ग्रासरूट हीरोज, हेरिटेज कंजर्वेशन और वाइल्ड लाईफ कंजर्वेशन की श्रेणियों में पुरस्कार दिये जाएंगे।

26वाँ राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह

चर्चा में क्यों ?

12 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान में जयपुर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल कैंपस, मानसरोवर में 26वाँ राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति व विकास कार्यों के लिये उल्लेखनीय दान कार्य करने वाले 350 से अधिक दानदाताओं तथा प्रेरकों को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें लगभग 246 दानदाता एवं 108 प्रेरक सम्मिलित रहे।
- इस सम्मान समारोह में गत 3 वर्षों में शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले दानदाताओं को शामिल किया गया। इसमें इन तीन वर्षों में किसी एक वर्ष में एक करोड़ रुपए या अधिक का दान देने वालों को 'शिक्षा विभूषण' के रूप में सम्मानित किया गया तथा अन्य को 'शिक्षा भूषण' के रूप में सम्मानित किया गया।
- इस अवसर पर डॉ.कल्ला ने भामाशाहों व उनको प्रेरित करने वाले प्रेरकों को संबोधित करते हुए परहित का काम करने पर साधुवाद ज्ञापित किया तथा स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने भी शिक्षा के क्षेत्र में भामाशाहों के योगदान की महत्ता को बताया।

राजस्थान में पेयजल की गुणवत्ता जाँच के लिये स्थापित होंगी 250 नई प्रयोगशालाएँ

चर्चा में क्यों ?

13 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य के विभिन्न ज़िलों में पंचायत समिति स्तर पर पेयजल की गुणवत्ता जाँच के लिये 250 नई प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने पेयजल की गुणवत्ता एवं जल संरक्षण को लेकर आमजन में जागरूकता पैदा करने तथा ब्लॉक स्तर पर स्थापित होने वाली लैब के लिये भवन चिह्नित करने में तेज़ी लाने के निर्देश दिये।
- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि नई प्रयोगशालाएँ स्थापित होने से पानी की गुणवत्ता में और सुधार करते हुए आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में आसानी होगी।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में प्रदेश के 32 ज़िलों में ज़िलास्तरीय प्रयोगशालाएँ एवं जयपुर में राज्य स्तर की प्रयोगशाला कार्यरत् हैं।
- संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 20 ज़िलों में आउटसोर्स पर आधारित मोबाइल लैब पानी की गुणवत्ता जाँच कर रही हैं। इनमें जोधपुर एवं उदयपुर रीज़न में 6-6 तथा कोटा एवं अजमेर रीज़न में 4-4 मोबाइल लैब कार्यरत् हैं।

नोट :

- विदित है कि जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष अभी तक 10 हज़ार 689 फील्ड टेस्ट किट, 7 लाख 52 हज़ार 207 जीवाणु जाँच किट वितरित की गई हैं तथा ग्राम जल स्वच्छता समितियों के सदस्यों को पानी की गुणवत्ता जांच का प्रशिक्षण देने के लिये ज़िला रसायनज्ञ एवं फील्ड अभियंताओं द्वारा 1421 शिविर आयोजित किये गए हैं। अप्रैल से लेकर अभी तक 91 प्रतिशत केमिकल टेस्टिंग तथा 48 प्रतिशत जीवाणु जाँच की गई हैं। 20 मोबाइल लैब के माध्यम से 86 प्रतिशत सैंपल टेस्टिंग की गई हैं।

राजस्थान को 67 वर्ष बाद मिला राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी की मेज़बानी का अवसर

चर्चा में क्यों ?

13 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड द्वारा आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जंबूरी की तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य को 67 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी की मेज़बानी का अवसर प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का आयोजन राज्य के पाली ज़िले के रोहट में 4 से 10 जनवरी, 2023 तक किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह जम्बूरी राज्य में स्काउट एवं गाइड का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा।
- उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्वास्थ्य, चरित्र, कला एवं कौशल, सेवा भावना तथा अनुशासन जैसे गुणों का विकास होता है तथा सामाजिक समरसता, सौहार्द्र, सद्भावना व आपसी भाईचारे की भावना का भी संचार होता है, जिससे विभिन्न देशों व राज्यों की संस्कृतियों को समझने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा।
- जम्बूरी से पूर्व एवं जम्बूरी के दौरान विभिन्न माध्यमों द्वारा नियमित रूप से व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जम्बूरी स्थल पर प्रदर्शनियां भी आयोजित होंगी। साथ ही, जम्बूरी स्थल पर प्रतिदिन राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी होंगे।
- शिक्षा विभाग द्वारा सम्भागियों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। साथ ही, जम्बूरी स्थल पर अस्थाई पुलिस चौकी, यातायात व्यवस्था, नियमित पेट्रोलिंग एवं सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड की मेज़बानी में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में 1500 विदेशी सहित पूरे देश से 35 हज़ार से अधिक स्काउट एवं गाइड हिस्सा लेंगे।
- इस 7 दिवसीय जम्बूरी में स्टेट द्वार, पायनियरिंग प्रोजेक्ट, एडवेंचर वैली, ग्लोबल विलेज डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन गेम्स, मार्च पास्ट, कलर पार्टी, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग एवं वाटर एक्टिविटीज जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
- शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि जम्बूरी स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाओं का विस्तार समयबद्ध रूप से पूर्ण हो जाएगा तथा इस आयोजन के लिये एक स्मारिका भी प्रकाशित की जाएगी।
- राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड के प्रधान व पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि मुख्यमंत्री के विज़न के अनुरूप यह विश्वस्तरीय आयोजन हो रहा है। इससे राजस्थान की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ेगी।

जस्टिस पंकज मिथल बने राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों ?

14 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस पंकज मिथल को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। जस्टिस मिथल राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं।

प्रमुख बिंदु

- जस्टिस पंकज मिथल ने हिन्दी भाषा में शपथ ली। इससे पहले जस्टिस पंकज मिथल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।

नोट :

- जस्टिस पंकज मिथल का कार्यकाल लगभग 8 महीने रहेगा। वो 16 जून, 2023 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे।
- जस्टिस पंकज मिथल का जन्म 17 जून, 1961 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। वर्ष 1982 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और वर्ष 1985 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े मेरठ के एक कॉलेज से एलएलबी कोर्स किया।
- इन्होंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में प्रेक्टिस शुरू की। 7 जुलाई, 2006 को पहली बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जज के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली। वर्ष 2021 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए।
- राजस्थान उच्च न्यायालय में यह तीसरा मौका है, जब मुख्य न्यायाधीश पद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किसी जज ने पदभार संभाला है। पहली बार वर्ष 1949 में जस्टिस के.के. वर्मा इस पद पर नियुक्त हुए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे वर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। वे 29 अगस्त, 1950 से 24 जनवरी, 1950 तक इस पद पर रहे। इसके बाद 26 जनवरी, 1950 को देश में संविधान लागू होने के बाद मुख्य न्यायाधीश पद पर कैलाश नाथ को नियुक्ति मिली।
- विदित है कि 1 अगस्त, 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसएस शिंदे सेवानिवृत्त हो गए थे, तब से जस्टिस एमएम श्रीवास्तव काम संभाल रहे थे।
- सितंबर 2022 के आखिरी सप्ताह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित की अध्यक्षता में हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में जस्टिस पंकज मिथल का ट्रांसफर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 11 अक्टूबर को जस्टिस पंकज मिथल का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में करने का आदेश निकाला।

मुख्यमंत्री ने दी पृथ्वीराज नगर के लिये 747 करोड़ रुपए की पेयजल योजना को स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

16 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के पृथ्वीराज नगर के लिये पेयजल योजना के फेज-प्रथम (स्टेज द्वितीय) एवं फेज-द्वितीय के कार्यों हेतु 747.08 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि जयपुर के पृथ्वीराज नगर और इसके आस-पास के क्षेत्र को बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना से जोड़ा जा रहा है।
- पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति के इस निर्णय से 145 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में वितरण तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा एवं विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर का आंशिक क्षेत्र सम्मिलत होंगे।
- इनमें जयपुर नगर निगम ग्रेटर के 10 वार्ड (पूर्ण) तथा 8 वार्ड (आंशिक) हैं। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र बगरू एवं विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा के कुल 15 ग्राम भी हैं।
- गौरतलब है कि पहले चरण (फेज-प्रथम, स्टेज-प्रथम) में 563.93 करोड़ रुपए की लागत के कार्य शुरू हैं, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पृथ्वीराज नगर क्षेत्र और आसपास आबादी क्षेत्र के विस्तार के तहत तथा आने वाले समय में जनता की दूरगामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 'बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना' शुरू की है।

भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान-2022

चर्चा में क्यों ?

16 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान की समर्पण संस्था द्वारा जयपुर में आयोजित समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह में सिक्किम के पूर्व राज्यपाल जस्टिस एस. एन. भार्गव ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को 'भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान-2022' से सम्मानित किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को कला एवं संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिये इस सम्मान से सम्मानित किया गया है।
- संस्थापक अध्यक्ष डॉ. दौलतराम माल्या ने बताया कि पन्नालाल मेघवाल की कला एवं संस्कृति में बारह पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं तथा राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में 500 से अधिक आलेख प्रकाशित हुए हैं।
- उन्होंने बताया कि उनकी पुस्तकों एवं आलेखों से देश-विदेश के सुधि पाठक, कला एवं संस्कृति प्रेमी, शोधार्थी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी अध्ययन करके लाभान्वित हो रहे हैं।
- डॉ. दौलतराम माल्या ने बताया कि मेघवाल की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के मांड गीत, राजस्थान शिल्प सौंदर्य प्रतिमान, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम, दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रचलित लोक नृत्य, राजस्थान हस्तशिल्प कलाएँ, दी हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान कथौड़ी जनजाति, राजस्थान कला एवं संस्कृति के विविध आयाम और राजस्थान कथौड़ी जनजाति कला एवं परंपरा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

ऊर्जा मंत्री ने सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

17 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भँवर सिंह भाटी ने विद्युत भवन में 'सौर कृषि आजीविका योजना' के पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- यह पोर्टल किसानों एवं विकासकर्त्ताओं को किसानों की बंजर/अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में मदद करेगा।
- भँवर सिंह भाटी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यरूप से कृषि भार वाले लोड सेंटर पर पीएम-कुसुम कम्पोनंट-सी (फीडर लेवल सोलराईजेशन) के तहत विकसित किये जा रहे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिये राज्य सरकार ने सौर कृषि आजीविका योजना तैयार की है।
- उन्होंने बताया कि इस योजना के पोर्टल को लाँच करने का उद्देश्य यह है कि किसानों को सोलर के माध्यम से अपने नज़दीक के 33/11 जीएसएस से दिन में बिजली प्राप्त हो सके। इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से किसानों व भूमि मालिकों को सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये पूर्व निर्धारित राशि के आधार पर अपनी बंजर/अनुपयोगी भूमि को लीज़ पर देने का अवसर देकर राज्य के प्रचुर भूमि संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।
- भाटी ने बताया कि इस ऑनलाईन पोर्टल पर किसी भी गाँव में 33/11 केवी जीएसएस के आसपास के किसान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिये अपनी ज़मीन को लीज़ पर देने हेतु पंजीकृत कर सकते हैं और सौर ऊर्जा संयंत्र के विकासकर्त्ता भी पंजीकृत किसानों/भूमि मालिकों तक पहुँचने के लिये पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते है।
- उन्होंने बताया कि सोलर प्लांट की स्थापना के बाद 33/11 केवी जीएसएस के आसपास के जितने भी कृषि उपभोक्ता हैं, उन सभी को सोलर के माध्यम से दिन के समय अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिलेगी और उनकी बिजली की समस्या का समाधान होगा।
- उन्होंने बताया कि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कुसुम कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराईजेशन) के तहत् इस योजना में केंद्रीय वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है।
- प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स भास्कर ए.सावंत ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में ये प्लांट लगेंगे। इस योजना में छोटे प्लांट लगेंगे, जिससे उत्पादित बिजली का लाभ प्लांट के आसपास के क्षेत्र के किसानों को ही मिलेगा।
- इस योजना के तहत् जिन क्षेत्रों में कृषि बिजली का भार अधिक है, उन जीएसएस को चिह्नित करके पीएम-कुसुम योजना-सी में फीडर लेवल सोलराईजेशन के तहत् संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।

नोट :

- उन्होंने बताया कि अभी 781 जीएसएस चिह्नित किये हैं जहाँ कृषि लोड ज़्यादा है, जिन पर 971 प्रोजेक्ट लग सकते हैं और इनसे 3079 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे 2 लाख 71 हज़ार पंप सोलराइज हो जाएंगे।
- विदित है कि अभी एमएनआरई ने एक लाख पंप की स्वीकृति दी है, जिसे धीरी-धीरे 2 लाख पंप सोलराइजेशन तक ले जाया जाएगा।
- इस पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पोर्टल पर किसान द्वारा अपनी भूमि का पंजीकरण करने के पश्चात् विकासकर्त्ता देख पाएगा कि कितनी भूमि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये कास्तकार ने पोर्टल पर पंजीकृत की है। सभी सूचनाएँ पोर्टल पर मिलने से सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।
- उन्होंने बताया कि किसानों को समय पर पूरी लीज राशि मिलने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत डिस्कॉम को दी जाने वाली बिजली का भुगतान विकासकर्त्ता को किये जाने वाले भुगतान में से डिस्कॉम द्वारा लीज़ राशि काट कर सीधे कास्तकार को भुगतान किया जाएगा व शेष राशि का भुगतान विकासकर्त्ता को किया जाएगा।

राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित जयपुर में सिटी पार्क का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

17 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जयपुर के मानसरोवर में विकसित सिटी पार्क का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 21 अक्टूबर को लोकार्पण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- आवासन आयुक्त ने बताया कि इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रथम चरण में मध्यम मार्ग पर निर्मित भव्य एंट्री प्लाजा का गुंबदनुमा स्टील स्ट्रक्चर, आकर्षक फाउंटेन तथा राजस्थान का सबसे ऊँचा (213 फीट) राष्ट्रीय ध्वज एवं इसके निकट करीब 2 हज़ार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मनोरम लोअर लेक इस पार्क की प्रमुख विशेषता हैं।
- पार्क में 20 फीट चौड़ा एवं 3.5 कि.मी. लंबा जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, जिस पर भ्रमण करते हुए लोग आकर्षक लाइटिंग एवं म्यूजिक का आनंद ले सकेंगे।
- प्रथम चरण के कार्यों के लिये 61.31 करोड़ रुपए के कुल 34 कार्यादेश जारी किये गए, जिनके विरुद्ध 54.99 करोड़ रुपए की राशि से इन सभी कार्यों को पूरा कर लिया गया है।
- आवासन आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण में फाउंटेन स्क्वायर, वी.टी. रोड, अरावली मार्ग एवं न्यू सांगानेर रोड पर एंट्री प्लाजा, बॉटेनिकल गार्डन, एक्सपोजिशन ग्राउंड, जयपुर चौपाटी की तर्ज़ पर फूड कोर्ट का निर्माण तथा 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अपर लेक के कार्य निर्माणाधीन हैं, जिनकी पूर्णता पर 58.54 करोड़ रुपए की राशि व्यय होना संभावित है।
- उन्होंने बताया कि करीब 52 एकड़ भूमि पर विकसित इस पार्क के बनने से मानसरोवर एवं इसके आस-पास की कॉलोनियों में बसे लाखों लोगों को स्वच्छ आबोहवा मिलेगी। यहाँ 32 विभिन्न प्रजातियों के 25 हज़ार फूलदार एवं फलदार पौधे तथा लगभग 40 हज़ार फुलवारी लगाए गए हैं। इस पार्क में जापानी मियावाकी पद्धति से पौधारोपण किया गया है।
- आवासन आयुक्त ने बताया कि सिटीपार्क के लोकार्पण के अलावा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में राज्य के 11 विभिन्न शहरों की 15 आवासीय योजनाओं में निर्मित 2967 आवासों का लोकार्पण भी करेंगे। मंडल द्वारा आवंटियों को इन आवासों का कब्ज़ापत्र दिया जाएगा।
- ये आवास वाटिका एवं महला आवासीय योजना (जयपुर) तथा महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना फेज प्रथम एवं द्वितीय बड़ली (जोधपुर) के साथ ही नसीराबाद, किशनगढ़, निवाई, आबू रोड, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, भिंडर तथा बांसवाड़ा जैसे छोटे शहरों की योजनाओं में बनाए गए हैं।
- इनमें ज्यादातर मकान ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के हैं। इससे ज़रूरतमंद वर्ग का लोगों के घर का सपना साकार हो सकेगा।

नोट :

अस्पतालों में स्थापित होंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

चर्चा में क्यों ?

18 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पतालों के लिक्विड एवं सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिये बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 20 करोड़ रुपए के बजट को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री गहलोत की इस स्वीकृति से प्रदेश के बड़े अस्पतालों आरयूएचएस, एसएमएस अस्पताल, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय जयपुर, महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर, पीबीएम अस्पताल बीकानेर तथा चिकित्सा महाविद्यालय कोटा से संबद्ध अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होंगे तथा अस्पतालों के लिक्विड एवं सॉलिड वेस्ट का निस्तारण किया जा सकेगा।
- पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण आरयूआईडीपी द्वारा किया जाएगा। प्लांट के निर्माण के लिये लागत का 50 प्रतिशत व्यय चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा तथा 50 प्रतिशत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वहन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए लिक्विड एवं सॉलिड वेस्ट का निस्तारण करने के लिये प्रदेश के बड़े अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये जाने हेतु बजट में घोषणा की थी।

प्रदेश में 124 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुले

चर्चा में क्यों ?

18 अक्टूबर, 2022 को पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में विभिन्न ज़िलों में 124 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- लालचंद कटारिया ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार ने आदेश जारी कर पशु चिकित्साविहीन ग्राम पंचायतों में 124 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले हैं। नए उपकेंद्र खुलने से पशुपालकों को अपने नज़दीक ही बेहतर चिकित्सा सेवाएँ एवं विभागीय योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सकेगा।
- उन्होंने बताया कि जयपुर में 17, दौसा में 10, धौलपुर में 8, पाली में 7, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर एवं भरतपुर में 6-6, अलवर, डूँगरपुर, जालौर एवं जोधपुर में 5-5, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, नागौर एवं चित्तौड़गढ़ में 4-4, बाँसवाड़ा व टोक में 3-3, झुंझुनूं, सीकर, करौली एवं कोटा में 2-2 तथा बूंदी, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं प्रतापगढ़ में 1-1 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं।

प्रत्येक राजकीय भवन की होगी जिओ-टैगिंग

चर्चा में क्यों ?

18 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के विभिन्न विभागों व उपक्रमों की परिसंपत्तियों, योजनाओं एवं कार्यों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से जिओ-टैगिंग कर उन्हें मैप से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस हेतु प्रारंभ में 153.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से अब राज्यव्यापी जीआईएस प्रणाली के माध्यम से सभी विभाग अपनी परिसंपत्तियों, सुविधाओं, योजनाओं व कार्यक्रमों का भू-स्थानिक डाटा जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म से जोड़ सकेंगे। इससे संसाधन संग्रहण एवं वितरण, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के नीति नियोजन के संबंध में निर्णय लेने और उनके निरीक्षण में आसानी होगी।

नोट :

- उक्त निर्णय से विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के भू-चिह्नित सर्वेक्षण से क्षेत्रीय स्तर पर सेवा प्रदायगी बेहतर हो सकेगी। आपदा या महामारी के दौरान संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी इस प्रणाली के माध्यम से हो सकेगा। साथ ही, राज्य के सभी राजकीय भवन एक ही मैप पर उपलब्ध होंगे तथा आमजन के लिये इन भवनों तक पहुँचना आसान हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि जिओ-टैगिंग के अंतर्गत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। विभिन्न विभागों, जैसे- महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएचईडी, भू-जल विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आदि द्वारा ऐप का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।
- जीआईएस एक ऐसी प्रणाली है, जिसे पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक स्थितियों के संबंध में डाटा एकत्रित करने, संग्रहित करने, संशोधन करने तथा विश्लेषण करने के लिये बनाया गया है। साथ ही, इस प्रणाली से डाटा प्रबंधित करने तथा प्रस्तुत करने का कार्य भी किया जा सकता है।

राजस्थान के पुलिस विभाग में 500 मोबाइल यूनिट्स का होगा गठन

चर्चा में क्यों ?

19 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में 108 एंबुलेंस की तर्ज़ पर 500 नवीन मोबाइल यूनिट्स के गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि इन मोबाइल यूनिट्स को अभय कमांड सेंटर (डायल 100/डायल 112) से जोड़ा जाएगा तथा प्रत्येक यूनिट के लिये 1 हेड कॉन्सटेबल और 2 कॉन्सटेबल तैनात होंगे। इस प्रकार 24 घंटे हेतु 3 हेड कॉन्सटेबल व 6 कॉन्सटेबल की आवश्यकता होगी।
- उन्होंने बताया कि इन यूनिट्स के गठन हेतु 500 वाहन किराए पर लिया जाना प्रस्तावित है। इन यूनिट्स का संचालन पुलिस में उपलब्ध नफरी द्वारा किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पुलिस की दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा आमजन की समस्याओं के निराकरण में सुगमता होगी। इन मोबाइल यूनिट्स के गठन से पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ने के साथ ही आपराधिक घटनाओं में भी कमी आएगी।

'चंबल-धौलपुर-भरतपुर बृहद् पेयजल परियोजना' के सर्वे एवं डीपीआर कार्यों के लिये मिली वित्तीय स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

19 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'चंबल-धौलपुर-भरतपुर बृहद् पेयजल परियोजना' के तहत भरतपुर एवं धौलपुर ज़िलों में सर्वे एवं डीपीआर कार्यों के लिये राज्य मद से 7.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री गहलोत की इस स्वीकृति से परियोजना के सर्वे एवं डीपीआर कार्यों को गति मिलेगी तथा परियोजना के समयबद्ध रूप से पूर्ण होने पर भरतपुर एवं धौलपुर दोनों ज़िलों में घरेलू नल कनेक्शन के कार्य भी पूर्ण हो सकेंगें।
- 'चंबल-धौलपुर-भरतपुर बृहद् पेयजल परियोजना' के पूर्ण होने पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा, सिंचाई के लिये भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में पेयजल की सुचारु उपलब्धता के लिये 3 हज़ार 106 करोड़ रुपए की 'चंबल-धौलपुर-भरतपुर बृहद् पेयजल परियोजना' की घोषणा की थी।
- विदित है कि राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर, 2022 को उक्त परियोजना के प्रथम फेज हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

नोट :

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन

चर्चा में क्यों ?

20 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 अगस्त से राज्य में जोधपुर की लूणी पंचायत समिति से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि ग्रामीण ओलंपिक से देश में नया इतिहास रचा गया है। इसमें हर आयु वर्ग के 30 लाख से अधिक ग्रामीणों ने मैदान में दमखम दिखाया तथा लगभग 10 लाख महिलाओं ने हिस्सा लेकर ऊँची उड़ान भरीं।
- उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य में 1 माह 22 दिन तक आयोजित किये गए हैं। इस खेल में 6 खेल (कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिसबॉल क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबाल, हॉकी) शामिल किये गए तथा इसमें 30 लाख से अधिक हर आयु वर्ग के महिला-पुरुष तथा लगभग 3700 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में अपना खेल कौशल दिखाया।
- मुख्यमंत्री ने समापन समारोह में विजेता टीमों (प्रथम तीन स्थान) और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को ट्रॉफी, स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
- राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में विजेता रहे ज़िले व खिलाड़ी-

खेल	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कास्यं पदक	सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
कबड्डी (बालक)	चूरू	हनुमानगढ़	नागौर	सोनू
कबड्डी (बालिका)	हनुमानगढ़	नागौर	अजमेर	प्रियंका
वॉलीबाल (बालक)	चूरू	झुंझुनूं	चित्तौड़गढ़	संदीप
वॉलीबाल (बालिका)	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	चूरू	कविता
टेनिसबॉल क्रिकेट (बालक)	बीकाने	जैसलमेर	बांसवाड़ा	बिशनाराम
टेनिसबॉल क्रिकेट (बालिका)	जयपुर	अजमेर	उदयपुर	ज्वाला
हॉकी (बालक)	हनुमानगढ़	भीलवाड़ा	अजमेर	लवीश
हॉकी (बालिका)	हनुमानगढ़	चूरू	सीकर	नर्मदा
शूटिंग वॉलीबाल (बालक)	हनुमानगढ़	श्रीगंगानगर	जयपुर	जसविंदर सिंह
खो-खो (बालिका)	सीकर	बीकानेर	हनुमानगढ़	कंचन सामोता

- इस समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिये प्रमाण-पत्र भी सौंपा गया। यह प्रमाण-पत्र उन्हें राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में 30 लाख से अधिक खिलाड़ियों के शामिल होने और एक साथ पूरे प्रदेश में खेल आयोजन के लिये मिला।
- समापन समारोह के अवसर पर युवा मामले एवं खेल मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि राज्य में खिलाड़ियों को आउट-ऑफ-टर्न नियुक्तियाँ, नौकरियों में आरक्षण, पदक विजेताओं की सम्मान राशि में बढ़ोतरी सहित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं, जिससे राज्य में खिलाड़ियों की संख्या में भी इज़ाफा हो रहा है।
- समापन समारोह पर मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में अब 26 जनवरी से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन भी किया जाएगा।

राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

21 अक्टूबर, 2022 को भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सीआईआई एवं टाटा कम्यूनिकेशन सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को वर्ष 2022 के डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक डॉ. ओपी बैरवा ने बताया कि यह पुरस्कार राज्य को पहचान वेब एवं एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से जन्म, मृत्यु, विवाह एवं एमसीसीडी रजिस्ट्रेशन में आशातीत प्रगति के लिये दिया गया है।
- उन्होंने बताया कि पुरस्कार के लिये 400 से अधिक नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे, जिनमें से राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पहचान एंड्रॉयड वेब एप्लीकेशन को डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन पुरस्कार के लिये चुना गया।

राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23

चर्चा में क्यों ?

22 अक्तूबर, 2022 को राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा 'राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23' लागू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान राज्य बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर ने बताया कि किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा नव विकसित उन्नत किस्मों का उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उचित दर पर अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने एवं प्रमाणित बीजों के उपयोग मे बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 लागू की जा रही है।
- निगम किसानों के लिये उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उत्पादन कर उचित मूल्य पर ग्राम स्तर तक उपलब्ध करा रहा है। निगम द्वारा मुख्यत: खरीफ में मूंग, उड़द, ग्वार, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, बाजरा एवं रबी में गेहूँ, चना, सरसों एवं जौ के फसलों का बीज उत्पादन किया जा रहा है।
- यह योजना राज्य के सभी ज़िलों में क्रियान्वित की जाएगी तथा इस योजना पर कुल राशि रुपए 4.00 करोड़ व्यय किया जाएगा।
- इस योजना अंतर्गत प्रत्येक ज़िले में 51 उपहार किसानों को लॉटरी के माध्यम से प्रदान किये जाएंगे।
- प्रत्येक ज़िले में प्रथम उपहार स्वरूप ट्रैक्टर-1, द्वितीय उपहार बैट्री ऑपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर मशीन 20 एवं तृतीय उपहार किसान टॉर्च 30 का लॉटरी से चयन कर उपहार किसानों को वितरित किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य बीज निगम के द्वारा किसानों के लिये बीज क्रय पर उपहार जैसी महत्त्वपूर्ण योजना लागू किये जाने से किसानों में प्रमाणित बीजों के उपयोग के प्रति रुचि बढेगी और किसान प्रमाणित बीजों का अधिकाधिक उपयोग कर अधिक उत्पादन एवं अधिक आय अर्जित कर सकेंगे।

राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 लागू

चर्चा में क्यों ?

22 अक्तूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 'राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022' लागू करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। ये नियम राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों पर लागू होंगे।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के 1 लाख 10 हज़ार से भी अधिक संविदाकर्मियों को इन नियमों के दायरे में लाकर लाभान्वित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रवर्तित एवं राज्य सरकारों की विभिन्न जनकल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की क्रियान्विति में ये संविदाकर्मी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, लेकिन इनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ तक कि कई राज्यों में तो इनका मानदेय तक नहीं बढ़ाया गया।
- इस निर्णय से शिक्षा विभाग के शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम अध्यापक सहित कुल 41423 संविदाकर्मी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के राजीविका व मनरेगा के कुल 18326, अल्प संख्यक विभाग के 5697 मदरसा पैरा टीचर्स, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग के 44833 संविदाकर्मियों सहित कुल 1 लाख 10 हज़ार 279 संविदाकर्मी इन नियमों से लाभान्वित होंगे।

नोट :

- राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के लागू होने से संविदाकर्मियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो सकेगी तथा इसमें आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जो संविदाकर्मी 5 साल तक काम कर लेंगे, भविष्य में उन पदों के नियमित होने पर उन्हीं संविदाकर्मियों में से स्क्रीनिंग कर उन्हें स्थायी किया जा सकेगा।
- नियमों में यह भी ध्यान रखा गया है कि किस पद को किस स्थायी पद के समकक्ष माना जाए, इसी आधार पर इन संविदाकर्मियों के लिये मानदेय का निर्धारण किया गया है और स्पेशल पे प्रोटेक्शन का प्रावधान भी रखा गया है। नियमित होने पर इन कर्मियों को ओ.पी.एस. का लाभ भी दिया जाएगा।
- संविदाकर्मियों को नियमित करने को लेकर समय-समय पर कई कमेटियाँ बनीं, लेकिन इनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका।
- विदित है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में संविदाकर्मियों का विभागवार कैडर बनाने और वर्ष 2022-23 के बजट में इनके मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि किये जाने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान में विभिन्न बोर्ड के गठन को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

23 अक्तूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के समग्र विकास एवं आर्थिक उत्थान के लिये राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड तथा राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड की स्वीकृति से चर्म व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी एवं उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
- इस बोर्ड के गठन से राज्य के औद्योगिक विकास में इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी। साथ ही, उनके कार्यस्थल एवं विकास स्थल पर समस्त आधारभूत सुविधाओं यथा सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, उत्पादों के विपणन हेतु मार्केटिंग सेंटर विकसित हो सकेंगे।
- इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को आधुनिक तकनीक आधारित चर्म रंगाई एवं अन्य उत्पादों हेतु देश में प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी की जा सकेगी। बोर्ड के माध्यम से इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा हेतु योजनाएँ बनेंगी एवं उनका समयबद्ध क्रियान्वयन होगा।
- इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के विकास हेतु समुचित वित्तीय सहयोग एवं बैंकों से वित्त का प्रबंध भी हो सकेगा। चर्म उत्पादों की सरकारी खरीद में निविदा प्रक्रिया से मुक्त रखने का कार्य भी बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा। चर्म उत्पादों की खरीद व तकनीकी प्रोद्योगिकी में सहयोग के अलावा फुटवियर निर्माण एवं चर्म उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ज़िला/राज्य स्तर पर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनके वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्य किये जाएंगे। राजस्थान में पंजीकृत चर्म दस्तकार, बोर्ड में पंजीयन करवाकर योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
- राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड के गठन से काछी, कुशवाह, माली, सैनी इत्यादि बागवान समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक व शैक्षणिक स्तर में वृद्धि होगी। बोर्ड द्वारा इनकी आर्थिक अभिवृद्धि के लिये विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित की जाएंगी तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- इस बोर्ड के गठन से बागवान समाज के लिये विभिन्न विकास एवं कल्याण से संबंधित योजनाओं का प्रारूप तैयार हो सकेगा तथा इन वर्गों की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही उनके परंपरागत व्यवसाय को भी अधिक लाभदायक स्थिति में लाया जा सकेगा।
- रजक समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा इनकी समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिये सुझाव देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

नोट :

- राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का प्रशासनिक विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा तथा राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड व राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत होगा।
- इन बोर्ड के गठन से प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिये नवीन योजनाएँ बनाई जा सकेंगी तथा उनके उत्थान के लिये आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। इससे हर वर्ग का पिछड़ापन समाप्त हो सकेगा तथा हर वर्ग सर उठाकर जीवनयापन कर सकेगा।

राजस्थान के 344 आवासीय विद्यालयों में स्थापित होंगी डिजिटल लाइब्रेरी

चर्चा में क्यों ?

26 अक्टूबर, 2022 को डिजिटल लर्निंग के महत्त्व को समझते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिये 36.56 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात, स्कूल शिक्षा विभाग आदि के अधीन संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों, बहुद्देशीय हॉस्टल व कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा से लैस डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो सकेंगी।
- गौरतलब है की वित्त एवं विनियोग विधेयक, 2022-23 की चर्चा के दौरान की गई घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने यह स्वीकृति प्रदान की है।
- मुख्यमंत्री ने अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को डिजिटल लर्निंग का लाभ दिलाने की दृष्टि से विभिन्न विभागों के अधीन आवासीय शिक्षण संस्थानों एवं चयनित विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिये डिजिटल लाइब्रेरी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय प्रावधान की घोषणा की थी।
- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 मदरसों में अब स्मार्ट क्लासरूम करने के लिये 13.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की शुरुआत कर दी है। अब मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिये इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, यहाँ विद्यार्थी अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के ज़रिये तालीम (शिक्षा) हासिल करेंगे।
- राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में से 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किये जाने के लिये प्रति मदरसा 2.62 लाख रुपए खर्च होंगे।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2022-23 में पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम मय इंटरनेट की सुविधा चरणबद्ध रूप से कराए जाने की घोषणा की थी। इसी के तहत प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 500 मदरसों को अपग्रेड किया जाएगा।

राष्ट्रीय युवा योजना के सातदिवसीय राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना शिविर की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

26 अक्टूबर, 2022 को जाने-माने गांधीवादी विचारक स्वर्गीय डॉ. एस.एन. सुब्बाराव (भाई जी) द्वारा स्थापित राष्ट्रीय युवा योजना (एनवाईपी) द्वारा राजस्थान के जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में सातदिवसीय राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना शिविर की शुरुआत की गई।

प्रमुख बिंदु

- 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले इस अखिल भारतीय शिविर में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 500 से ज़्यादा स्वयं सेवक और जाने-माने गांधीवादी शिरकत कर रहे हैं।

नोट :

- पूर्व महाधिवक्ता जी.एस. बापना ने बताया कि 27 अक्टूबर को सुब्बाराव जी की पहली पुण्यतिथि है। पिछले साल इसी दिन जयपुर में उनका निधन हुआ था। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस बार यह शिविर जयपुर में आयोजित किया गया है।
- सुब्बाराव जीवनभर देश में भाईचारा, सद्भावना एवं प्रेम के प्रचार-प्रसार और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष के लिये युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से देश के कोने-कोने में शिविर आयोजित करते थे। उन्हीं के काम को आगे बढ़ाते हुए यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत के सभी राज्यों के साथ राजस्थान के सभी 33 ज़िलों से स्वयं सेवक हिस्सा ले रहे हैं।
- स्वर्गीय सुब्बाराव की याद में दुर्गापुरा गोशाला में राष्ट्रीय एकता बगीचा लगाया जाएगा, जिसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए सभी स्वयं सेवक एक-एक पौधा लगाएंगे।
- शिविर संयोजक हनुमान सहाय शर्मा के अनुसार इस शिविर में प्रतिष्ठित गांधीवादी विचारकों के व्याख्यान होंगे और व्यक्तित्व विकास पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्वधर्म प्रार्थना के बाद युवाओं को स्वानुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा।

ईसरदा पेयजल परियोजना के लिये 6 नए कार्यालयों के गठन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

26 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) के अंतर्गत ईसरदा पेयजल परियोजना के लिये 6 नवीन कार्यालयों के गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। ये कार्यालय दौसा ज़िले में खोले जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) के अंतर्गत ईसरदा पेयजल परियोजना का निर्माण दौसा व सवाई-माधोपुर ज़िलों में पेयजल आपूर्ति के लिये किया जा रहा है।
- 3651 करोड़ रुपए की ईसरदा पेयजल परियोजना से दोनों ज़िलों के 1256 गाँवों तथा 6 शहरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने 6 नवीन कार्यालयों में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के 1, अधीक्षण अभियंता के 1, अधिशासी अभियंता के 6, सहायक अभियंता के 14 सहित कुल 65 पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
- मुख्यमंत्री ने नवीन कार्यालयों में फर्नीचर व अन्य ज़रूरी सामान उपलब्ध कराने हेतु 18 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की है। उक्त स्वीकृति से ईसरदा जल परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी तथा समयबद्ध तरीके से योजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र में आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

राजस्थान में उद्योगों को ईटीपी लगाने के लिये 13.88 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी

चर्चा में क्यों ?

27 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 एवं 2019 के अंतर्गत राज्य में औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) की स्थापना के लिये 88 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में ईटीपी लगाने की स्वीकृति से विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्सर्जित किये जाने वाले अपशिष्ट का उचित उपचार किया जा सकेगा तथा पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी।
- राज्य में अधिक-से-अधिक उद्योगों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये यह योजना लाई गई है।
- ज्ञातव्य है कि ईटीपी लगने से जहाँ एक ओर हानिकारक औद्योगिक कचरे के निस्तारण में सहायता मिलती है, वहीं उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट से आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव होता है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) लगाने पर प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 20 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

डॉ. भीमराव अंबडेकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022

चर्चा में क्यों ?

27 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के उद्योग आयुक्त महेंद्र पारख ने उद्योग भवन में राज्य के समस्त बैंकों के राज्यस्तरीय नियंत्रक अधिकारीगणों के साथ आयोजित बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये डॉ. भीमराव अंबेडेकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- आयुक्त पारख ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9 फीसद ब्याज अनुदान तथा 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ ही 25 लाख रुपए तक की सीमा में प्रोजेक्ट लागत का 25 फीसद तक मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निवेशक नए उद्योग लगाने, सेवा क्षेत्र में तथा व्यापार के लिये भी प्रेरित होंगे।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में उद्योग विभाग ने 8 सितंबर, 2022 को इस योजना की अधिसूचना जारी कर दी थी।
- योजनांतर्गत लक्षित वर्गों की प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों सहित पात्र व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना या विस्तार के लिये विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता अनुदान एवं अन्य सुविधाओं संबंधी प्रावधान किये गए हैं, जिससे उक्त वर्गों का आर्थिक सशक्तीकरण हो सकेगा।
- इस योजना के अंतर्गत लक्षित वर्गों के उद्यमियों को उद्यमिता एवं कौशल संवर्धन कार्यक्रम, इन्क्यूबेशन सेंटर के माध्यम से प्रायोगिक प्रशिक्षण, रियायती दर पर भूमि की उपलब्धता व अन्य परिलाभ, कम लागत पर ऋण सुविधा, सीजीटीएमएमएसई के अंतर्गत गारंटी फीस मार्जिन मनी अनुदान, व्याज अनुदान सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।

राज्य में स्थापित होगा ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

चर्चा में क्यों ?

28 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिये 28 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान सरकार द्वारा राज्यवासियों को एक सुरक्षित एवं पारदर्शी ई-गवर्नेंस देने की प्रतिबद्धता के साथ राज्य में ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिये आगामी पाँच वर्षों हेतु 28 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
- विदित है कि अशोक गहलोत ने चालू वित्तीय वर्ष में 24 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिये आईआईआईटी कोटा से एमओयू किया जाएगा। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जन आधार रेजिडेंट डाटा रिपॉजिटरी आदि में पारदर्शिता एवं सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का विस्तार करते हुए ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के संबंध में घोषणा की गई थी।

नोट :

मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के प्रारूप को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

28 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के प्रारूप को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- इन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अशोक गहलोत द्वारा वक्फ संपत्ति संरक्षण योजना के लिये 5 करोड़ रुपए, आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिये 34 करोड़ रुपए तथा जनसहभागिता के आधार पर आधारभूत संरचना विकास कार्यों के लिये 10 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
- वक्फ संपत्ति संरक्षण योजना के अंतर्गत वक्फ भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि में बने कब्रिस्तान, मदरसों, विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण जैसे विकास कार्य किये जाएंगे। इन विकास कार्यों के किये जाने से वक्फ भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि को विवाद एवं अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकेगा।
- आधारभूत संरचना विकास कार्यों में राज्य में स्थित अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे तथा इन क्षेत्रों में पेयजल टंकी निर्माण, सड़क निर्माण, नाली निर्माण आदि विकास कार्य होने से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का समग्र विकास हो सकेगा तथा बस्तियों में जीवनयापन की स्थितियों को बेहतर बनाया जा सकेगा।
- जनसहभागिता आधारित संरचना विकास कार्यों में ऐसी वक्फ संपत्तियों का संरक्षण एवं विकास कार्य होगा, जहाँ 10 प्रतिशत जनसहभागिता हिस्साराशि प्राप्त हो जाती है। इस योजना के अंतर्गत वे सभी वक्फ संपत्तियाँ पात्र होंगी, जो राजस्व रिकॉर्ड/राजस्थान वक्फ बोर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हैं तथा योजना के तहत नवीन धार्मिक संपत्तियों का निर्माण कार्य शामिल नहीं होगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास एवं कल्याण हेतु अल्पसंख्यक समावेशी विकास कोष का गठन किये जाने की घोषणा की गई थी।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट

चर्चा में क्यों ?

29 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 (रिप्स-2022) के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत विकास में उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के लिये निरंतर प्रयासरत् है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से रिप्स-2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की गई विद्युत पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी। इकाइयों को उक्त छूट का लाभ रिप्स-2022 स्कीम के नियमानुसार मिल सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में उद्योगों के उचित विकास एवं निवेश के लिये बेहतर माहौल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में रिप्स-2022 योजना शुरू की गई है।

नोट :

जोधपुर में हुआ दो-दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

29-30 अक्टूबर, 2022 को जोधपुर में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा 'कंटेंपररी ज्यूडिशियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेन्थनिंग जस्टिस फॉर लॉ एंड टेक्नॉलॉजी' विषय पर राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी ऑडिटोरियम में पश्चिम क्षेत्र के पहले दो-दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन का उद्घाटन 29 अक्टूबर को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया।
- इस सम्मेलन में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक ए.पी. साही सहित राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
- राज्यपाल कलराज मिश्र ने न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि वे न्याय व्यवस्था ही नहीं, बल्कि संविधान से जुड़े कानूनों के भी मुख्य प्रहरी हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और इससे जुड़े नीतिगत विकास के ज़रिये देश में न्याय प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हो रहे कार्य अहम् हैं।
- उन्होंने विशेष अपेक्षा व्यक्त करते हुए देश में न्याय एवं विधि व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ ही आम जन के लिये न्याय को त्वरित एवं और अधिक सुगम तथा प्रभावी बनाने के हेतु बेहतर प्रयासों का आह्वान किया।
- उन्होंने लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ का समाधान खोजने के लिये आधुनिक तकनीकी उपकरणों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने, न्याय तंत्र को व्यापक स्तर पर सुदृढ़ करने, शीर्ष अदालत में मामलों को सूचीबद्ध करने के लिये भी सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित किये जाने, देश में आबादी का विस्तार के मद्देनज़र न्याय व्यवस्था के समक्ष बढ़ रही चुनौतियों से निपटने के लिये प्रभावी कार्य करने पर ज़ोर दिया।
- उन्होंने कहा कि देश की अदालतों में लाखों वाद लंबित हैं। न्याय में विलंब की इस समस्या को दूर करने के लिये बेहतर व्यवस्था कायम करने पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बने, जिससे छोटे-मोटे निर्णयों के त्वरित निदान की व्यवस्था से आम जन लाभान्वित हो, इस पर भी अकादमी को कार्य करने की आवश्यकता है।

नोट :